



ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी, पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्याएँ, लेख, सुझाव, प्रतिक्रियाएँ या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं हवाटसएप नंबर है।
greenrevolt2019@gmail.com
9798166006

कृषि परिवारों पर कर्ज भार में मामूली सुधार
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में 50 प्रतिशत से अधिक कृषि परिवार कर्ज में थे और प्रत्येक कृषि परिवार पर बकाया ऋण की औसत राशि 74,121 रुपये थी। 'स्थिति आकलन' के नवीनतम निष्कर्षों के अनुसार कृषि परिवार और ग्रामीण भारत में परिवारों की भूमि जोत, 2019' 10 सितंबर को जारी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक छह साल पहले 2013 में पेश किए गए सर्वेक्षण की तुलना में कर्ज में ढूँढे परिवारों का प्रतिशत 51.9 फीसदी से थोड़ा कम हुआ है वहीं, प्रत्येक कृषि परिवार ऋण की औसत राशि में 57 फीसदी की वृद्धि हुई है। छह साल पहले (2013) में औसत कर्ज 47,000 रुपये था। औसत बकाया ऋण के मामले में कुल 28 राज्यों में आंध्र प्रदेश (एपी) पर सबसे अधिक औसत बकाया 2.45 लाख रुपये का ऋण था।

राज्य के 5.85 लाख शहरी नागरिकों के लिए पेयजलापूर्ति का मार्ग प्रशस्त

●केंद्र, एडीबी और राज्य सरकार के बीच 1168 करोड़ रूपए का हुआ त्रिपक्षीय ऋण समझौता
●एडीबी देगा 817.60 करोड़ रूपया ऋण, राज्य सरकार 350.40 करोड़ देगी अपनी हिस्सेदारी
संवाददाता
रांची : झारखंड के सभी शहरी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये लगभग 5 लाख 85 हजार शहरी आबादी को पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराने की परियोजना मूर्त रूप लेने जा रही है। राज्य के शहरी विकास एवं जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बुधवार 8 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में केंद्र सरकार, एशियन डेवलपमेंट बैंक, राज्य सरकार और जुड़को के बीच 1168 करोड़ रुपये के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के अपर सचिव रजत कुमार मिश्रा, राज्य सरकार के नगर विकास विभाग की ओर से सुधा निदेशक सह परियोजना निदेशक, वायव्य संपोषित परियोजना प्रबंधन इकाई अमित कुमार, एशियन विकास बैंक के कंट्री डायरेक्टर तोकियो कोनिशी एवं जुड़को के उप परियोजना प्रबंधक उत्कर्ष मिश्रा द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे के निर्देश पर झारखंड शहरी जलापूर्ति उन्नयन परियोजना



(JUWSSIP) के अंतर्गत जुड़को लिमिटेड द्वारा एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण से शहरी जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इस परियोजना से राजधानी रांची के साथ ही राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े शहरों मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और झुमरीतिलैया को लाभ पहुंचेगा। प्रथम चरण में राज्य के चार शहरी निकायों रांची, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और झुमरीतिलैया में जलापूर्ति के लिए कुल 1168 करोड़ रुपये की परियोजना बनायी गयी है। इसके लिए एशियाई विकास बैंक प्रथम चरण के तहत 817.80 करोड़ रुपये का ऋण देगा जबकि राज्य सरकार की हिस्सेदारी लगभग 350.40 करोड़ रुपये होगी।
रांची के 304660 लोगों को मिलेगा शुद्ध पेयजल
इस परियोजना से रांची शहरी पेयजलापूर्ति फेज 2 ए के तहत 213 एमएलडी का रूकका में जलशोध संयंत्र के साथ ही बोडेया के भ्रम पहाड़ी पर एक जलमीनार बनाया जायेगा। इससे रांची नगर निगम क्षेत्र के 60932 आवासों यानि लगभग 304660 लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। फेज 2 ए के तहत हरिहर सिंह रोड, बरियातु, पहाड़ टोली, खलगांव, लोवाडीह, कोकर, चुटिया, नामकुम, अनंतपुर, नेपाली बस्ती डोरंडा, कृष्णापुरी, सिरमटोली, रांची स्टेन, खादगाड़ा, कांटाटोली, पुरुलिया रोड, अहीर-टोली, लोअर बाजार, चर्च रोड, कर्बला चौक, अशोक नगर और अरगोड़ा क्षेत्र को जलापूर्ति का लाभ मिलेगा। इस योजना पर 756 करोड़ रुपये खर्च होंगे। रांची के रूकका में 88 करोड़ की लागत से एक 225 एमएलडी का इंटेक वेल भी बनाया। इस इंटेक वेल से रांची की सभी जलापूर्ति योजनाओं को पेयजल मिलेगा।

झुमरीतिलैया के 125000 लोगों को मिलेगा शुद्ध जल
झुमरीतिलैया शहरी परियोजना के तहत लगभग 25000 आवासों यानि 125000 लोग शुद्ध पेयजल से लाभान्वित होंगे। तिलैया डैम पर इंटेकवेल बनेगा। इसके अलावा 35.5 एमएलडी जलशोध संयंत्र तथा चार नये जलमीनार बनाये जायेंगे। पहले से निर्मित चार जलमीनारों एवं एक 10 एमएलडी के जलशोध संयंत्र का भी उपयोग किया जायेगा। इस योजना में कुल 200 किलोमीटर पाइप लाइन बिछायी जायेगी। योजना की लागत 150 करोड़ रुपये है।
हुसैनाबाद के 34515 लोगों को मिलेगा शुद्ध पेयजल
हुसैनाबाद शहरी जलापूर्ति योजना के तहत 6303 आवासों यानि 31515 लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस योजना के तहत सोन नदी पर 9.50 एमएलडी का इंटेकवेल बनेगा। 60 किलोमीटर कुल पाइप लाइन बिछाई और चार नये जलमीनार बनेंगे। यहां पहले से पांच जलमीनार और एक जलशोध संयंत्र उपलब्ध है। 215 किलोमीटर पाइप लाइन बिछायी जायेगी। इस योजना की लागत लगभग 162 करोड़ रुपये है। परियोजनाएं वर्ष 2028 तक पूरी की जानी है। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड द्वारा इस परियोजना को पहले ही सहमति दी जा चुकी है। एशियाई विकास बैंक के साथ पिछले 11 जन को इस परियोजना से संबंधित लोन नेगोसियेशन भी हो चुका है।

सीसीएल में उत्खनन अभियंता बन शिवानी ने इतिहास रचा



रांची संवाददाता : सीसीएल की चूरी भूमिगत खदान में कुछ दिन पूर्व सुश्री आकांक्षा कुमारी ने जब एक माइनिंग इंजीनियर के रूप में खदान में योगदान देने वाली पहली महिला के लिए वह एक ऐतिहासिक दिन था। इस घटना से देश के कोयला खनन उद्योग के इतिहास में एक नया अध्याय खुला जब एक महिला कर्मी ने एक चुनौतीपूर्ण भूमिका में पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज की। यह घटना निश्चय ही दीर्घकालीन समयकाल में एक नयी दिशा देने वाला था। अब राजस्थान की रहने वाली शिवानी मीणा ने सीसीएल के रजरणा क्षेत्र की मेकेनाइज्ड खुली खदान, रजरणा परियोजना में अपना योगदान दिया। यह अविस्मरणीय व अभूतपूर्व है क्योंकि शिवानी एक्सकवेशन (उत्खनन) कैडर की पहली महिला इंजीनियर हैं जो खुली खदान में कार्य करेंगी। उन्हें भारी मशीनों (एचईएमएम) के रख-रखाव एवं मरम्मत की जिम्मेदारी दी गयी है। रजरणा क्षेत्र सीसीएल की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। रजरणा क्षेत्र को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है। आईआईटी जोधपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुकी, सुश्री शिवानी ने कोयला जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज कर कर उदहारण प्रस्तुत किया है। भूमिगत खदान के उपरांत अब खुली खदान में महिला इंजीनियर ने योगदान देकर कोयला खनन में महिला सशक्तिकरण को संबल दिया है। भारत सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में प्रदान किये गए अवसर का समुचित लाभ लेते हुए इन महिलाओं ने न सिर्फ उम्मीदों का एक नया द्वार खोला है बल्कि अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनी है। सीसीएल ही नहीं कोल इण्डिया लिमिटेड के इतिहास में यह एक गौरव का पल है। महिला सहकर्मियों ने कम्पनी में विभिन्न भूमिकाओं को बखूबी निभा रही हैं। वह अब सीसीएल की कोयला खदानों में भी पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर कोयला उत्पादन कर देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति हेतु सक्रिय भूमिका निभा रही है। राजस्थान की रहने वाली शिवानी ने शुरू से ही एक मेधावी छात्रा रही हैं और इंजीनियरिंग के प्रति उनकी रूचि और झुकाव शुरू से ही रही है।

बीएयू में तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन



संवाददाता
उलीहातू गाँव के 30 आदिवासी किसान हो रहे हैं शामिल
रांची : बिस्सा कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा समेकित कृषि प्रणाली के विभिन्न आयामों के उपयुक्त उन्नत तकनीकी मॉडल से आदिवासी किसानों की आजीविका सुदृढ़ एवं आय में बढ़ोतरी विषयक तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण बुधवार को शुरू हुआ। कार्यक्रम में विवि द्वारा अंगीकृत बिस्सा भगवान की जन्मस्थली उलीहातू गाँव के करीब 30 आदिवासी किसान भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव ने कहा कि प्रदेश के 80 प्रतिशत से भी अधिक किसान छोटे एवं सीमांत श्रेणी के हैं। जो किसानों के कम आय के होने को मुख्य वजह है। विवि वैज्ञानिकों द्वारा इन किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिये समेकित कृषि प्रणाली के अनेकों मॉडल को विकसित किया गया है। ये तकनीकी किसानों के आय बढ़ोतरी में काफी उपयोगी साबित हो रही है। डीन फॉरेस्ट्री डॉ एमएस मल्लिक ने ग्रामीण विकास में कृषि वानिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला। कहा कि नवीनतम तकनीक एवं उन्नत प्रजाति की से बांस की खेती को उलीहातू गाँव में बढ़ावा दिया जा रहा है। अपर निदेशक, प्रसार शिक्षा डॉ एस कर्मकार ने कहा कि बीएयू वैज्ञानिकों द्वारा झारखण्ड प्रदेश के उपयुक्त अनेकों लाभकारी तकनीकों का समावेश कर समेकित कृषि प्रणाली मॉडल को विकसित किया गया है। इस आवासीय प्रशिक्षण में किसानों को बांस की खेती, जैविक खेती, फसल विविधकरण, आधुनिक कृषि यंत्र, पोषण वाटिका, मुदा स्वास्थ प्रबंधन, मशरूम उत्पादन, मछली पालन, कुककूट पालन, सूकर पालन एवं मधुमच्छी पालन आदि विषयों की व्यावहारिक तकनीकों से रूबरू कराया जायेगा। मौके पर शायर वैज्ञानिक डॉ शोला बारला ने भी अपने विचारों को रखा। कार्यक्रम के पहले दिन किसानों को डॉ सीएस सिंह ने समेकित कृषि प्रणाली का महत्त्व एवं प्रदेश के उपयुक्त उन्नत तकनीकी, डॉ मांजिद अंसारी ने सब्जी उत्पादन की नवीनतम तकनीकी, डॉ पंकज सेठ ने पशुपालन की उन्नत तकनीकी एवं प्रबंधन तथा डॉ बन्धु उरॉव ने मुर्गीपालन एवं बत्ख पालन की उन्नत तकनीकी एवं प्रबंधन के बारे में बताया। स्वागत भाषण डॉ पंकज सेठ एवं धन्यवाद डॉ बन्धु उरॉव ने दी। कार्यक्रम संचालन में राजेश कुमार एवं निर्मल कुमार ने सहयोग दिया।

पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता व्यापारिक तनाव

अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता व्यापारिक तनाव न केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है, साथ ही वो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है।



ललित मोर्य
अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता व्यापारिक तनाव न केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है, साथ ही वो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यह न केवल उन दोनों देशों के पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, साथ ही अन्य देशों के पर्यावरण पर भी दबाव डाल रहा है। हाल ही में इस विषय पर किए एक नए अध्ययन से पता चला है कि जिस तरह से इन दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है उसके चलते चीन ने अमेरिका से आयात किए जाने वाले कृषि उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया है नतीजतन सोयाबीन जैसी फसलों के आयात में कमी आई है, जिस वजह से अमेरिका में किसानों को इन फसलों के स्थान पर कहीं ज्यादा प्रदूषण करने वाली फसलों की तरफ जाना पड़ा है जो सोयाबीन के मुकाबले कहीं ज्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदूषण करती हैं। साथ ही उनकी सिंचाई के लिए कहीं ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है जो वहां पानी की मांग में भी वृद्धि का कारण बन रहा है। यदि देखा जाए तो इस के प्रभाव केवल दो देशों के बीच में ही सीमित नहीं रहते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से अन्य देशों में भी फैल जाते हैं। इसका असर अतिरिक्त दबाव के रूप में पहले से ही तनाव झेल रहे पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे की ब्राजील के अमेजन आदि पर पड़ता है। यदि 2017 के आंकड़ों को देखें तो उस वर्ष में चीन ने अमेरिका से करीब 145,740 करोड़ रुपए (1,960 करोड़ डॉलर) मूल्य के कृषि उत्पादों का आयात किया था। नतीजतन चीन, अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए एक प्रमुख खरीदार बन गया था। इन अमेरिकी कृषि निर्यातों में से 86 फीसदी फसल उत्पाद थे। जिनमें से 74 फीसदी सोयाबीन था। वहीं यदि 2018 से जुड़े आंकड़ों को देखें तो चीन द्वारा

कृषि उत्पादों पर लगाए शुल्कों के चलते सीधे तौर पर अमेरिकी किसानों पर असर पड़ा था, इसके कारण अमेरिका से चीन के कुल कृषि आयात में लगभग 74,358 करोड़ रुपए (एक हजार करोड़ डॉलर) की गिरावट आई थी, जिसने विशेष रूप से सोयाबीन को प्रभावित किया था। व्यापारिक संबंधों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले असर पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जो सीधे तौर पर पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं। चीन अपनी जरूरतों के लिए अमेरिका से जो फसल आयात करता है उससे अमेरिका के पर्यावरण पर दबाव बढ़ गया है, 2014 से 2016 के दौरान चीन को निर्यात की जाने वाली फसलों के उत्पादन के लिए अमेरिका में औसतन 1.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर फसलें उगाई थी। साथ ही इनके लिए 4 लाख करोड़ लीटर साफ पानी की जरूरत पड़ी थी। साथ ही इसके लिए 50 करोड़ किलोग्राम

नाइट्रोजन और 70 लाख किलोग्राम अतिरिक्त फास्फोरस की जरूरत पड़ी थी वहीं अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए चीन अपने देश में वर्तमान तकनीकों की मदद से फसल का उत्पादन करता तो उसके लिए उसे 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर फसलें उगानी पड़ती। इसके लिए 9 लाख करोड़ लीटर साफ पानी की जरूरत पड़ती। साथ ही इसके लिए चीन को 170 करोड़ किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 करोड़ किलोग्राम फास्फोरस की जरूरत पड़ती। इस तरह देखा जाए तो चीन ने फसलों का जो आयात किया था उससे करीब 80 लाख हेक्टेयर भूमि और 5 लाख करोड़ लीटर पानी की बचत हुई थी। साथ ही इससे 120 करोड़ किलोग्राम नाइट्रोजन और 29.3 करोड़ किलोग्राम फास्फोरस के उपयोग में कमी आई थी, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। वहीं यदि चीन अपनी सोयाबीन की मांग को पूरा करने के लिए ब्राजील का रुख करता है तो उसके चलते ब्राजील में फसलों में होने वाला बदलाव नाइट्रोजन प्रदूषण और पानी की मांग को कम कर देगा पर साथ ही वो फास्फोरस प्रदूषण और जंगलों की कटाई की वजह बन सकता है।

बंगाल: मवेशियों के दूध, अंडे और गोशत में भी मिले आर्सेनिक

उबले हुए अंडे के सफेद हिस्से में आर्सेनिक की मौजूदगी 9.7-30.6 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम मिली और पीले हिस्से में 9.78-22.1 माइक्रोग्राम प्रति किलो आर्सेनिक मौजूद था। भूगर्भ जल और अनाज में आर्सेनिक की मौजूदगी तो कई शोधों में सामने आ चुकी है, लेकिन अब एक नये शोध में मवेशियों के दूध, मुर्गियों के अंडे व बकरी के गोशत में भी आर्सेनिक की मौजूदगी का पता चला है। 'आर्सेनिक टॉक्सिसिटी इन लाइवस्टॉक ग्रोइंग इन आर्सेनिक एंडेमिक एंड कंट्रोल साइट्स ऑफ वेस्ट बंगाल: रिस्क ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंट' नाम से छपे शोधपत्र में बताया गया है कि गाय के दूध में प्रति लीटर 3.29-13 माइक्रोग्राम तक आर्सेनिक मिलता है। वहीं, बकरियों के दूध में 6.12-9.51 माइक्रोग्राम प्रति लीटर आर्सेनिक पाया गया है। आर्सेनिक एक रसायन है, जो गंगा के मैदानी इलाकों में भूगर्भ में पाया जाता है। इसका रिसाव होने से ये भूगर्भ जल में मिल गया है। इस रसायन के अत्यधिक सेवन से लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। यह शोध पत्र जादवपुर विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ



एनवायरमेंटल स्टडीज की तरफ से तैयार किया गया है, जिसे ए. दास, एम ज्वा-रदार, एनआर चौधरी, ए. डे, डी. मुधा शामिल ने तैयार किया। शोध का नेतृत्व स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज रिसर्च व प्रोफेसर डॉ तरित राय चौधरी ने किया। डॉ तरित ने बताया, 'उबले हुए अंडे के सफेद हिस्से में आर्सेनिक की मौजूदगी 9.7-30.6 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम मिली और पीले हिस्से में 9.78-22.1 माइक्रोग्राम प्रति किलो आर्सेनिक मौजूद था। इसी प्रकार मुर्ग के गोशत में 51.2-163 माइक्रोग्राम/किलो (सूखा हुआ) और लिबर में 118-328 माइक्रोग्राम (प्रति किलो के हिसाब से) आर्सेनिक मिला है। वहीं, बकरे के गोशत में 89 से 124 माइक्रोग्राम प्रति किलो के हिसाब से आर्सेनिक पाया गया है।' शोध के लिए आर्सेनिक से ग्रस्त हावड़ा, मिदनापुर, उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिलों से 30 मवेशी, 15 बकरियाँ और 10 मुर्गियाँ तथा सरकारी हस्तक्षेप वाले इलाकों से 10 मवेशियों का चयन किया गया था। शोध से पता चला है कि मवेशियों के शरीर में आर्सेनिक का प्रवेश पेयजल के अलावा सरसों की खली, धान के पुआल, धान के छिलके, गेहूँ के भूस से भी हो रहा है। कृषि उत्पादों में हालांकि आर्सेनिक की पुष्टि बहुत पहले हुए शोधों में की जा चुकी है। यहां ये भी बता दें कि

बंगाल में सबसे ज्यादा आर्सेनिक प्रभावित बसाहटें: देश के 15 जिलों की 6061 बसाहटों के भूगर्भ जल में सामान्य से ज्यादा आर्सेनिक मौजूद है। इनमें से 50 प्रतिशत बसाहटें सिर्फ पश्चिम बंगाल में हैं। इस साल 18 मार्च को जलशक्ति मंत्रालय की तरफ से एक सवाल के जवाब में बताया गया कि पश्चिम बंगाल की 3115 बसाहटें आर्सेनिक से बुरी तरह प्रभावित हैं। 2291 बसाहटों के साथ असम दूसरे और 385 बसाहटों के साथ बिहार तीसरे स्थान पर है। मनुष्य के शरीर में सामान्य से ज्यादा आर्सेनिक की मौजूदगी के निशान शरीर के बाहरी हिस्से में साफ दिख जाता है, इससे शरीर में काले चकते हो जाते हैं। लेकिन मवेशियों में भौतिक संकेत नहीं मिलते हैं। बल्कि, सामान्य से ज्यादा आर्सेनिक की मौजूदगी के चलते मवेशियों का वजन घटने लगता है, उनकी प्रजनन क्षमता घट जाती है और पेट की तकलीफें जैसी शिकायतें नजर आने लगती हैं। कितनी चिंताजनक है ये रिपोर्ट गौरतलब हो कि पौष्टिक आहार के रूप में मवेशियों के दूध के साथ-साथ मीट का सेवन किया जाता है। स्कूलों में मिड डे मील में अंडे भी शामिल हैं। चावल, गेहू व

माँ भवानी ट्रेडर्स
रातू रोड, कब्रिस्तान गेट नंबर 2 के सामने, रांची
फोन नंबर : 7677883037, 9460500631

हमारे यहां मछली की दवायें एवं तालाब के उपचार से संबंधित दवायें उपलब्ध हैं। टॉक्सीमाट, क्लीनर, सोकिना, ओ2मैक्स व अन्य सभी दवायें। मतस्यपालन से संबंधित सलाह एवं अन्य सामग्री हेतु अवश्य संपर्क करें

अहमदाबाद में 2020 की तुलना में इस बार मछर जनित बीमारियों में 110 प्रतिशत की बढ़ोतरी एजिसियां : कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में इन दिनों बच्चे और व्यस्क बुखार का शिकार हो रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर डेंगू - चिकनगुनिया की पहचान हो रही है लेकिन कई जगहों पर बुखार को एक मिस्ट्री ही बताया जा रहा। डेंगू से बचाव के लिए स्थानीय स्तर पर जो कवायद की जानी थी वह कमी कई जगह सामने आ रही है। गुजरात के अहमदाबाद में भी कुछ यही हाल है।

अहमदाबाद नगर निगम ने 9 सितंबर को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मच्छरों से होने वाली बीमारियों के आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक 2020 की तुलना में इस वर्ष डेंगू के मामले तीन गुना बढ़ गए हैं। जनवरी - सितंबर, 2020 में नगर निगम ने डेंगू के 255 मामले दर्ज किए थे जबकि इस वर्ष 684 डेंगू के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं, बीते वर्ष कालरा का कोई केस नहीं था जबकि इस वर्ष अब तक 64 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं, 2020 में जनवरी - सितंबर के दरमियान चिकनगुनिया के 196 केस निगम ने रजिस्टर किए थे। इस वर्ष यह दोगुनी होकर 412 हो गई है। इसी तरह मलेरिया के मामले भी बढ़े हैं। गौर करने लायक यह है कि यह आंकड़े केवल सरकारी अस्पताल के हैं। यदि इनमें प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती और इलाज करने वाले मरीजों की संख्या जोड़ी जाए तो रुग्ण लोगों की संख्या लगभग दस गुना हो जाएगी। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने यह दावा किया था कि उनका राज्य पूरी तरह से कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को तैयार है। लेकिन इस बीच डेंगू के कहर ने नगर निगम और सरकार की पोल खोल दी है।

शहर में इन दिनों मच्छरों और गंदगी से फैलने वाली बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। नगर निगम ने पिछले वर्ष सितंबर तक 2156 लोगों के सीम सैंपल लिए थे जबकि इस वर्ष अब तक मात्र 441 लोगों के ही सीम सैंपल लिए गए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में बलद सैंपल में भी कमी आई है।

राज्य के कृषि विकास में बीएयू की भूमिका अहम : बादल



वरीय संवाददाता

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा संकाय में अनुक्रम आधारीत नियुक्ति पत्र वितरण, उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह का हुआ आयोजन

रांची सांसद संजय सेठ ने बीएयू को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर से भेजने और केंद्र सरकार में हस्तभवन प्रयास एवं सहयोग देने की बात कही।

रांची : कृषि मंत्री बादल ने कहा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका राज्य में कृषि विकास के क्षेत्र में अविस्मरणीय रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों की दशा और दिशा बदलने में बीएयू की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। वे आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय प्रांगण में आयोजित अभिनन्दन समारोह में बोल रहे थे।

बादल ने कहा कि राज्य में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। किसानों को कृषि यंत्र के साथ-साथ बीज का वितरण व किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि विवि के तकनीकी विकास एवं तकनीकी हस्तांतरण तथा तय मानकों के अनुरूप सरकार सहयोग करेगी। छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं प्लेसमेंट के अवसर की दिशा में प्रयास होंगे। मंत्री जी ने कहा कि झारखण्ड आदिवासी बहुल राज्य है। इनके हितों की रक्षा एवं कृषि विकास हेतु पक्ष एवं विपक्ष के संयुक्त प्रयास से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने बीएयू की स्थापना में स्व. कार्तिक उराव के योगदान के बारे में बताया और

उनके नाम से संस्थान की स्थापना की बात रखी। कहा कि राज्य का विकास एवं दिशा कृषि से ही बदलेगा। कृषि विभाग एवं विश्वविद्यालय हरेक स्तर पर अधिकाधिक बिरसा किसानों को कृषि तकनीकी से जागरूक एवं समृद्ध करें। किसानों का विश्वास जीता जाय और कृषि उत्पादों का किसानों को मुनासिब मूल्य मिले। उन्होंने प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्रों को 5 हजार किसानों को जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करने की सलाह दी।

पहली बार कृषि मंत्री बादल के आगमन पर बीएयू कुलपति डॉ ओएन सिंह ने उनका अभिनन्दन किया। समारोह में कृषि मंत्री द्वारा विवि के मृत कर्मियों के 22 आश्रितों को अनुकंपा पर आधारित नियुक्ति - पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। जिसके परिणाम जल्द देखने को मिलेंगे। देश एवं राज्य की बहुतायत आबादी कृषि पर निर्भर है। देश के जीडीपी में कृषि का औसत योगदान 17 प्रतिशत और राज्य के जीडीपी में कृषि का औसत योगदान 12 प्रतिशत मात्र है। उन्होंने कहा कि केंद्र में कृषि का बजट मात्र 7 प्रतिशत एवं राज्य में 5 प्रतिशत है। इसमें सुधार के लिए अधिकार एवं कर्तव्य बोध पर ध्यान देने होगा।

मौके पर रांची सांसद संजय सेठ ने बीएयू को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर से भेजने और केंद्र सरकार में हस्तभवन प्रयास एवं सहयोग देने की बात कही। उन्होंने कहा कि झारखण्ड कृषि मामलों में, विशेषकर सब्जी उत्पादन में काफी समृद्ध है। जिसे आगे बढ़ाने एवं पंचायत स्तर पर कृषि शो केस स्थापित करने की जरूरत है।

कांके विधायक समरीलाल ने प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय पर खास



पशु चिकित्सा संकाय में उद्घाटन एवं शिलान्यास



पशु चिकित्सा संकाय में भवनों का उद्घाटन एवं शिलान्यास अभिनन्दन समारोह के बाद पशु चिकित्सा संकाय में उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल जी ने राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान के अधीन निर्मित पशु उत्पादन, प्रबंधन एवं निर्देशात्मक पशुधन फार्म भवन, 350 छात्रों की क्षमता वाली परीक्षा भवन तथा बड़ा एवं छोटा पशु प्रयोग गृह का उद्घाटन किया। मंत्री के द्वारा पशु चिकित्सा संकाय में आधुनिक पशु जांच एवं अल्पपरीक्षण प्रयोगशाला केंद्र का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने गो-पालन : एक नया आयाम नामक पुस्तक का विमोचन किया।

मौके पर डीन वेटनरी डॉ सुशील प्रसाद ने पशु चिकित्सा संकाय की गतिविधियों को बताया एवं धन्यवाद ज्ञापन दी। कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ, विधायक समरीलाल, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीक, कृषि निदेशक निशा उरांव, पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा, कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह एवं विवि के डीन, डायरेक्टर, प्रोफेसर, स्टाफ एवं किसान आदि मौजूद थे।

ध्यान देने की आवश्यकता जोर दिया। उन्होंने विवि में गृह विज्ञान कॉलेज खोलने तथा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की दर्जा दिलाने की मांग रखी।

पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने विवि के प्रगति के अवलोकन को भावुक क्षण बताया। उन्होंने विवि द्वारा स्व. कार्तिक उरांव के सपनों को पूरा करने की दिशा में किसानों को अधिकाधिक तकनीकी लाभ देने, सूदूर ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या का निराकरण करने तथा विवि में बड़े क्षमतावाली ऑटोटेरियम का निर्माण करने की सलाह दी। कृषि सचिव अबू बकर

सिद्दीक ने कहा कि हमारे समाज में कृषि का कोई विकल्प नहीं है। राज्य में पिछले वर्ष सबसे अधिक उत्पादन हुआ। दलहन उत्पादन के मामले में राज्य अग्रणी है। राज्य कृषि विकास में बीएयू की अग्रणी भूमिका रही है। विवि को पशुपालन, मत्स्य एवं वानिकी तकनीकी के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना होगा।

स्वागत भाषण में कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने विगत एक वर्षों में विवि की उपलब्धियों को रखा। कार्यक्रम का शिलान्यास शशि सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ ए वदूद ने दी।

रोजगार सृजन के लिये मेकॉन ने सिपेट से हाथ मिलाया



संवाददाता

रांची : मेकॉन ने गोद लिए गए गांवों के युवाओं के लिए "कौशल विकास और रोजगार सृजन" के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट), हेहल, रांची के साथ हाथ मिलाया है

मेकॉन ने अपने "कौशल विकास और रोजगार सृजन" के सीएसआर कार्यक्रम के तहत "मशीन ऑपरेटर (प्लास्टिक प्रसंस्करण / इंजेक्शन मॉल्डिंग)" पर "सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हेहल, रांची" में गोद लिए गांव राय और सुंगी के युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने की व्यवस्था की है। वर्तमान में, मेकॉन उपरोक्त गोद लिए गए गांवों के 7 (सात) युवाओं को "6 महीने के मशीन ऑपरेटर (प्लास्टिक प्रसंस्करण / इंजेक्शन मॉल्डिंग) पाठ्यक्रम" के लिए प्रायोजित कर रहा है। 7 युवकों में से दो लड़कियां हैं, जिन्होंने उपरोक्त पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए गहरी रुचि दिखाई है।

छात्रों के प्रायोजन की कुल लागत लगभग रु. 7.19 लाख है। उद्घाटन समारोह का आयोजन 07.09.2021 को सीआईपीईटी, हेहल, रांची के परिसर में किया गया था। श्री प्रवीण बी. बखव, संयुक्त निदेशक और प्रमुख, सीआईपीईटी ने आर.एच. जुनेजा, निदेशक (वित्त) और संजय कुमार, कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट सेवाएं) और नोडल अधिकारी (सीएसआर) का स्वागत किया। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन आरएच जुनेजा ने मेकॉन के उच्च अधिकारियों, मेकॉन की सीएसआर टीम, सीआईपीईटी के संकाय सदस्यों और ग्रामीण युवाओं की उपस्थिति में किया। कार्यक्रम के दौरान, युवाओं ने अपना परिचय दिया और उसके बाद निदेशक (वित्त), मेकॉन और संयुक्त निदेशक और प्रमुख, सीआईपीईटी ने युवाओं को संबोधित किया। वी. विग्ना, श्रीमती ए. टोप्पो और सीएसआर टीम के अन्य सदस्य, जिन्होंने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने और कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में विशेष प्रयास किया, वे भी उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

राज्य सरकार एवं सीसीएल के सहयोग से चेशायर होम में टीकाकरण

संवाददाता रांची : 09 सितम्बर को बरियातू, रांची स्थित 'चेशायरहोम' में राज्य सरकार एवं सीसीएल के सहयोग से कोविड टीकाकरण किया गया। चेशायर होम में रह रहे बरिष्ठ नागरिक एवं संस्था के कर्मचारियों सहित कुल 84 लोगों, जिनमें 17 को प्रथम डोज तथा 67 लोगों को दूसरा डोजका कोविड टीकाकरण किया गया। चेशायर होम में रह रहे सभी लोगो ने सीसीएल प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुये प्रबंधन का सहदय सराहना किया। टीकाकरण कार्यक्रम में सीसीएल के चिकित्सक डॉ. अंजना झा, सीएसएमएस (सीएसआर), डॉ. आर.के. सिंह, नोडल अधिकारी, डॉ. संजय कुमार, राज्य सरकार की ओर से दीप नारायण, सुचित्रा कुजूर एवं अन्य का सक्रिय योगदान रहा।

ज्ञातव्य है कि सीसीएल प्रबंधन द्वारा चेशायर होम में समय-समय पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता रहता है साथ ही अन्य सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है।

सीएमपीडीआई में दो दिवसीय फुटबॉल मैच का शुभारंभ



संवाददाता

रांची 11 सितम्बर: गोदवाना क्लब सीएमपीडीआई (मुख्यालय) द्वारा संस्थान के खेल मैदान में दिनांक 11.09.2021 से 12.09.2021 तक 2 दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया।

सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं कोल इंडिया के निदेशक (तकनीकी) विनय दयाल ने इस दो दिवसीय मैच का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्रीमती ज्योति दयाल] सीएमपीडीआई के निदेशक (तकनीकी/सीआरडी/ईएस) एस0के0

गोमास्ता, श्रीमती संगीता राणा की गरिमामय उपस्थिति रही। इस टूर्नामेंट के पहले लीग मैच में आज 8पीएम तथा ब्लैक हॉक के बीच मुकाबला हुआ। कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और दोनों टीमों बराबरी पर रही। दूसरे लीग मैच में बजरंगी बनाम माइनिंग यूनाइटेड के बीच मुकाबला हुआ।

बजरंगी की टीम माइनिंग यूनाइटेड को 3-1 से पराजित किया। बजरंगी की टीम की ओर से मंजूर वली ने 2 एवं जयंत ने 1 गोल कर अपनी टीम को जीत दिलायी। जवाब में माइनिंग

यूनाइटेड की टीम की ओर से शरण ने मात्र एक किया। तीसरे लीग मैच में माइनिंग यूनाइटेड का मुकाबला ब्लैक हॉक से हुआ। दोनों टीमों एक-एक गोलकर बराबरी पर रही।

माइनिंग यूनाइटेड की ओर से रवीश ने एक गोल किया जबकि जवाबी टीम ब्लैक हॉक की ओर से शरण ने एक गोल किया। चौथे लीग मैच में बजरंगी टीम का मुकाबला 8पीएम से हुआ। 8 पीएम ने बजरंगी को 1-0 से पराजित किया। इस लीग मैच में 8पीएम की ओर से देवाशीष ने एक गोल किया।

स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार

संवाददाता

यात्रियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किए गये हैं।

ट्रेन संख्या 02835 हटिया - यशवंतपुर (द्वि-साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन दिनांक 28/09/2021 से दिनांक 28/12/2021 तक प्रत्येक रविवार एवं मंगलवार को हटिया से चलेगी।

ट्रेन संख्या 02836 यशवंतपुर झ हटिया (द्वि-साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन दिनांक 30/09/2021 से दिनांक 30/12/2021 तक प्रत्येक मंगलवार एवं गुरुवार को यशवंतपुर से चलेगी।

ट्रेन संख्या 02812 हटिया - लोकमान्य तिलक टर्मिनस (द्वि-साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन दिनांक 25/09/2021 से दिनांक 31/12/2021 तक प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को हटिया से चलेगी।

ट्रेन संख्या 02811 लोकमान्य तिलक टर्मिनस - हटिया (द्वि-साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन दिनांक 27/09/2021 से दिनांक 02/01/2022 तक प्रत्येक रविवार एवं सोमवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलेगी।

ट्रेन संख्या 08626 हटिया - पूर्णिया कोर्ट स्पेशल ट्रेन दिनांक 29/09/2021 से दिनांक 31/12/2021 तक प्रतिदिन हटिया से चलेगी।

ट्रेन संख्या 08625 पूर्णिया कोर्ट - हटिया स्पेशल ट्रेन दिनांक 30/09/2021 से दिनांक 01/01/2022 तक प्रतिदिन पूर्णिया कोर्ट से चलेगी।

ट्रेन संख्या 02803 रांची - हावड़ा स्पेशल ट्रेन दिनांक 29/09/2021 से दिनांक 31/12/2021 तक प्रतिदिन रांची से चलेगी। ट्रेन संख्या 02804 हावड़ा - रांची स्पेशल ट्रेन दिनांक 30/09/2021 से दिनांक 01/01/2022 तक प्रतिदिन हावड़ा से चलेगी।



ट्रेन संख्या 08624 हटिया - इस्लामपुर स्पेशल ट्रेन दिनांक 29/09/2021 से दिनांक 31/12/2021 तक प्रतिदिन हटिया से चलेगी।

ट्रेन संख्या 08623 इस्लामपुर - हटिया स्पेशल ट्रेन दिनांक 30/09/2021 से दिनांक 01/01/2022 तक प्रतिदिन इस्लामपुर से चलेगी।

ट्रेन संख्या 02583 हटिया - आनंद विहार टर्मिनल (त्रि-साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन दिनांक 04/10/2021 से दिनांक 30/12/2021 तक प्रत्येक सोमवार, मंगलवार एवं गुरुवार को हटिया से चलेगी। ट्रेन संख्या 02584 आनंद विहार टर्मिनल - हटिया (त्रि-साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन दिनांक 05/10/2021 से दिनांक 03/01/2022 तक प्रत्येक मंगलवार, बुधवार एवं शुक्रवार को आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी।

ट्रेन संख्या 02579 हटिया - आनंद विहार टर्मिनल (त्रि-साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन दिनांक 01/10/2021 से दिनांक 31/12/2021 तक प्रत्येक रविवार, बुधवार एवं शुक्रवार को हटिया से चलेगी।

ट्रेन संख्या 02580 आनंद विहार टर्मिनल - हटिया (त्रि-साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन दिनांक 02/10/2021 से दिनांक 01/01/2022 तक प्रत्येक सोमवार, गुरुवार एवं शनिवार को आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी।

ट्रेन संख्या 08637 हटिया - बंगलुरु कैंट (साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन दिनांक 02/10/2021 से दिनांक 25/12/2021 तक प्रत्येक शनिवार को हटिया से चलेगी।

ट्रेन संख्या 08638 बंगलुरु कैंट - हटिया (साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन दिनांक 05/10/2021 से दिनांक 28/12/2021 तक प्रत्येक मंगलवार को बंगलुरु कैंट से चलेगी।

उपरोक्त सभी ट्रेनें पूर्णतः आरक्षित रहेंगी तथा इनके समय सारणी, कोच संयोजन एवं टहराव पूर्ववत् रहेंगे।

दुनिया के सबसे लुप्तप्राय और अनोखे भेड़ियों में से एक है भारतीय भेड़िया

अध्ययन का निष्कर्ष है कि भारतीय भेड़ियों परियामी एशियाई भेड़ियों से अलग हैं और यह भी दर्शाता है कि वे पहले जितना सोचा गया था उससे काफी कम क्षेत्र में फैले हुए हैं।

एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने पहली बार भारतीय भेड़ियों के जीनोम के अनुक्रम का अध्ययन किया है। अध्ययन से पता चला है कि भारतीय भेड़ियों पहले जितना सोचा गया था उसकी तुलना में कहीं अधिक खतरे में हैं। यह अध्ययन कैलिफोर्निया शहर के डेविस में स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है। भारतीय भेड़ियों को दुनिया के सबसे लुप्तप्राय और विकासवादी रूप से अलग भूरे या ग्रे भेड़ियों की आबादी में से एक है। अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय भेड़ियों, भेड़ियों के सबसे प्राचीन जीवित वंश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। भारतीय भेड़ियों तराई भारत और पाकिस्तान तक ही सीमित है, जहां इसके रहने वाले घास के मैदानों को भूमि रूप से मानव अतिक्रमण और मूछ के उपयोग में बदलाव से खतरा है।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ वेटनरी मेडिसिन की स्तनधारी पारिस्थितिकी संरक्षण इकाई के डॉक्टर लॉरेन हेनेली ने कहा कि भेड़ियों पाकिस्तान में आखिरी शेष बड़े



मांसाहारियों में से एक है और भारत के कई बड़े मांसाहारी खतरे में हैं। उन्होंने यह जानकर उम्मीद जताई कि वे इतने अनोखे हैं और केवल वहां पाए जाते हैं, स्थानीय लोगों और वैज्ञानिकों को इन भेड़ियों और घास के मैदानों के संरक्षण के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करेंगे।

अध्ययनकर्ताओं ने चार भारतीय और दो तिब्बती भेड़ियों के जीनोम को अनुक्रमित किया और उनके विकासवादी और फाईल जेनोमिक इतिहास को हल करने के लिए 31 अतिरिक्त केनिड जीनोम शामिल किए। उन्होंने पाया कि तिब्बती और भारतीय भेड़ियों एक दूसरे से और अन्य भेड़ियों की आबादी से अलग हैं। अध्ययन में सिफारिश की गई है कि भारतीय और तिब्बती भेड़ियों की आबादी को क्रमिक रूप से महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप में

मान्यता दी जानी चाहिए, एक अंतरिम पदानाम जो उनके संरक्षण को प्राथमिकता देने में मदद करेगा, जबकि उनके वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संरक्षण जीवविज्ञानी, सह-अध्ययनकर्ता खिलाल हबीब ने कहा यह अध्ययन इन परिदृश्यों में प्रजातियों के बने रहने महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम यह महसूस कर सकते हैं कि जिस प्रजाति के साथ हम परिदृश्य साझा कर रहे हैं, वह आज जीवित सबसे दूर का और सबसे अलग भेड़िया है।

भारतीय और पश्चिमी एशियाई भेड़ियों की आबादी को वर्तमान में एक ही आबादी की तरह देखा जाता है। अध्ययन का यह निष्कर्ष कि भारतीय भेड़ियों पश्चिमी एशियाई भेड़ियों से

अलग हैं, यह दर्शाता है कि पहले की तुलना में बहुत दूर तक नहीं फैले हैं।

एक प्राचीन वंश

भूरे या ग्रे भेड़ियों दुनिया में सबसे अधिक फैले हुए भूमि के स्तनधारियों में से एक हैं, जो उत्तरी गोलार्ध के बर्फ, जंगलों, रेगिस्तान और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। भेड़ियों हिमयुग से कठिन संघर्ष करते अभी भी बच हुए हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले इन भेड़ियों के रिफ्यूजिया कहा जाता है, जो संभावित रूप से अलग-अलग विकासवादी वंशों में बदल रहे हैं। परमाणु डीएनए जिसमें भेड़ियों के विकासवादी इतिहास को दर्शाने वाले लगभग सभी जीन शामिल थे। इससे पता चला कि भारतीय भेड़िया संभवतः तिब्बती भेड़ियों से भी काफी अलग था। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में स्तनधारी और पारिस्थितिकी संरक्षण इकाई के

निदेशक और अध्ययनकर्ता बेन सैक्स ने कहा, केवल माइटोकॉन्ड्रियल अनुक्रमण ही पर्याप्त नहीं था। परमाणु डीएनए बड़ी तस्वीर है और यह तस्वीर को बदल देता है। आप मान सकते हैं कि भूरे भेड़ियों की अधिकांश अनुवांशिक विविधता उत्तरी क्षेत्र में है, जहां आज अधिकांश भेड़ियों पाए जाते हैं। लेकिन यह अध्ययनकर्ता के रूप में विकासवादी विविधता को बरकरार रखती है और ये भी सबसे संकटग्रस्त हैं।

द्वानाधि

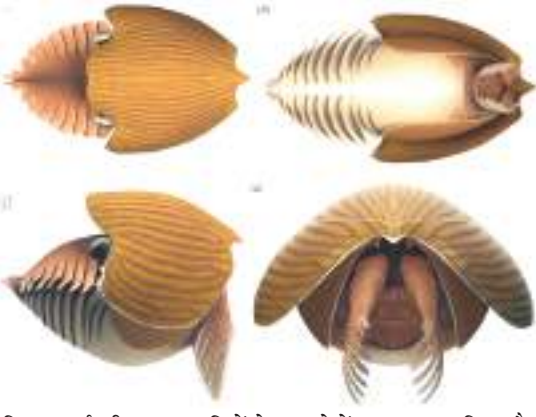
Quality With देव मेडिसिन्स

आप के प्यारे पेट्स पशुधन, जानवरों की सारी दवाईयां, वेक्सिन फूड एवं सभी एक्सेसरीज उपलब्ध।

रात रोड, नियर मेट्रो गली रांची फोन :9334935339

50 करोड़ वर्ष पुराने बर्जेस शैल में खोजी गई नए पशु की विशाल प्रजातियां

टाइटोकोरिज गेनेसी नाम की यह नई प्रजाति का आकार अद्भुत है। इसकी लंबाई लगभग आधा मीटर है, यह उस समय समुद्र में रहने वाले अधिकांश जानवरों में से एक विशाल जानवर था।



असुरों साल पुराने बर्जेस शैल में खोजी गई नई पशु की विशाल प्रजातियां फोटो : रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस, टाइटोकोरिज गेनेसी फोटो : रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस, टाइटोकोरिज गेनेसी शोधकर्ताओं ने कनाडा के रॉकीज में कूटने नेशनल पार्क से 50 करोड़ वर्ष पुरानी कैम्ब्रियन चट्टानों में एक विलुप्त पशु समूह से संबंधित एक विशाल नई जीवाश्म प्रजातियों के अवशेषों का खुलासा किया है। यह शोध रॉयल ऑस्ट्रेलिया संग्रहालय (रोम) के पैलियोन्टोलॉजिस्टों की अगुवाई में किया गया। यहां बताया चले कि बर्जेस शैल को इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के कारण 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था।

टाइटोकोरिज गेनेसी नाम की यह नई प्रजाति का आकार अद्भुत है। इसकी लंबाई लगभग आधा मीटर है, टाइटोकोरिज उस समय समुद्र में रहने वाले अधिकांश जानवरों में एक विशाल जानवर था, जिनमें से अब अधिकांश मुश्किल से एक छोटी उंगली के आकार तक पहुंच गए हैं। रोम के रिचर्ड एम. इनवर्टब्रेट पैलियोन्टोलॉजी के क्यूरेटर जीन-बर्नार्ड केरन कहते हैं कि इस जानवर का आकार विशाल है, यह कैम्ब्रियन काल के अब तक के सबसे बड़े जानवरों में से एक है।

विकासवादी वादी विचार से कहें तो, टाइटोकोरिज आदिम आर्थ्रोपोड्स के एक समूह से संबंधित है जिसे रेडियोडोटस कहा जाता है। इस समूह का सबसे प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सुव्यवस्थित शिकारी एनोमालोकारि-स है, जो स्वयं लंबाई में एक मीटर तक पहुंच सकता है। सभी रेडियो डॉन्ट की तरह, टाइटोकोरिज की आंखें बहुआयामी अर्थात् यह चारों ओर देख सकता था। इसका मुंह एक अनासास के टुकड़े के आकार का है, जिसमें दांत लगे होते हैं जो शिकार को पकड़ने के लिए उसके सिर के नीचे काटेदार पंजे की एक जोड़ी और तैयकी के लिए फ्लैप की एक श्रृंखला थी। इस समूह के भीतर, कुछ प्रजातियों में बड़े, विशिष्ट सिर वाले कवच धारी (कार्पस) भी थे, जिनमें से टाइटोकोरिज अब तक के सबसे बड़े पहचाने गए जानवरों में से एक है।

शोधकर्ता हेड्स ने बताया कि टाइटोकोरिज रेडियोडोटस के एक उप समूह का हिस्सा है, जिसे ह-डीडस कहा जाता है, जिसकी विशेषता एक अविश्वसनीय रूप से लंबे सिर से होती है, जो तीन-भाग वाले कार्पस या कवच से ढका होता है जो असंख्य आकार लेता है। सिर शरीर के सापेक्ष इतना लंबा होता है कि ये जानवर वास्तव में आसानी से तैर सकते थे।



हर साल सड़े-गले पेड़ों से 11 गीगाटन कार्बन निकलता है

दयानिधि
अध्ययन के अनुसार सड़े-गले या मृत पेड़ों से होने वाला उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन से होने वाले उत्सर्जन के लगभग 115 प्रतिशत के बराबर है।

दुनिया भर में जंगल वातावरण से काफी मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसलिए हमारे जलवायु की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, वैश्विक कार्बन चक्र में सड़े-गले या मृत पेड़ों की भूमिका के बारे में बहुत कम जानकारी है। लकड़ी का अपघटन या नष्ट होना और इसमें शामिल पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण (रीसायकल) जंगलों में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। दुनिया भर में सड़ने वाली लकड़ी से कितना कार्बन निकलता है? इस प्रक्रिया में कौन क्या भूमिका निभाते हैं? इन सवालों के जवाब के लिए अब बवेरियन फॉरेस्ट नेशनल पार्क द्वारा स्थापित एक वैश्विक शोध परियोजना में अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन जूलियस मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ वूर्जबर्ग (जेएमयू) और टैक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्युनिख (टीयूएम) के सहयोग से किया गया है।

छह महाद्वीपों के 55 जंगलों पर शोधकर्ताओं ने अपघटन या नष्ट होने की दर पर जलवायु के प्रभाव का आकलन करने के लिए 140 से



अधिक वृक्ष प्रजातियों की लकड़ी को चुना। आधी लकड़ी को जालीदार पिंजरों में रखा गया था। इन पिंजरों ने कीड़ों को अपघटन में शामिल होने से रोका और लकड़ी के अपघटन या नष्ट होने में उनके योगदान की मात्रा निर्धारित की। एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि अपघटन या नष्ट होने की दर और कीड़ों का योगदान जलवायु पर अत्यधिक निर्भर है और तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। गर्म क्षेत्रों में अधिक बारिश अपघटन की प्रक्रिया को तेज करती है और उन क्षेत्रों में इसे धीमा कर देता है जहां तापमान कम होता है।

असाधारण रूप से कठिन परिस्थितियों में दुनिया भर में 50 शोध समूहों ने तीन साल का प्रयोग पूरा किया। कुछ क्षेत्रों को हाथियों से बचाने के लिए विस्तृत उपायों का उपयोग करना आवश्यक था। एक इलाके के जंगल की आग से घिर गया था और वहां पुनर्निर्माण किया गया था, जबकि दूसरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। यह अध्ययन ने चर पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

अध्ययन के तकनीकी विश्वविद्यालय (टीयूएम) में पारिस्थितिक तंत्र गतिशीलता और वन प्रबंधन के प्रोफेसर रूफर्ट सोडल बताते हैं कि प्रयोग के आधार पर हम दुनिया भर के कार्बन चक्र में मृत पेड़ों की भूमिका के बारे में पता लगा सकते थे। अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर में मृत पेड़ों (डेडवुड) द्वारा हर साल लगभग 10.9 गीगाटन कार्बन से छोड़ा जाता है। इस संदर्भ में, कार्बन का एक हिस्सा मिट्टी में अवशोषित हो जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा वायुमंडल में मिल दिया जाता है। टीयूएम के वैज्ञानिक डॉ. वनर गमर कहते हैं, 'मृत पेड़ों से होने वाला उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन से होने वाले उत्सर्जन के लगभग 115 प्रतिशत के बराबर है। 193 प्रतिशत उष्णकटिबंधीय वन इस परिणाम में असमान रूप से योगदान करते हैं क्योंकि उनके लकड़ी के अधिक द्रव्यमान के कारण उनका तेजी से अपघटन या नष्ट होने की प्रक्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। समशीतोष्ण और बोरियल जंगलों में अपघटन काफी धीमा है, यह दर्शाता है कि इन क्षेत्रों में सड़े-गले या मृत पेड़ों से कार्बन को लंबे समय तक संग्रहीत किया जाता है।

जलकुंभी का कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे लोग असम की लड़कियों ने उसी से बना दिए योगा मैट



संचिता पाठक
जलकुंभी (Water Hyacinth) भारत के झीलों में बहुतायत में पाए जाते हैं। जलकुंभी अमेजन वर्षा वनों में पाया जाता था और पहले अंग्रेज गवर्नर जनरल की पत्नी **Lady Hastings** इसे भारत ले आईं, अब इसे टैर ऑफ बंगाल कहा जाता है। जलकुंभी पानी में मौजूद ऑक्सिजन ले लेती है और उस पानी में मछलियां और अन्य जलजीव नहीं बचते। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद आज तक जलकुंभी का कोई स्थाई समाधान नहीं निकल पाया है।

असम की 6 लड़कियों ने खोज लिया जल कुंभी का हल
असम के दिपोर बोल झील में भी जलकुंभी

एक साल की मेहनत के बाद बना योगा मैट
लगभग एक साल की मेहनत के बाद यह योगा मैट बनकर तैयार हुआ। इस मैट का नाम दिपोर झील पर आने वाली एक प्रवासी पक्षी, Purple Moorhen के नाम पर काम सोराई (Kaam Sorai) रखा गया है। मैट को बनाने, रंगने, बुनने की विधि ईको-फ्रेंडली है। ये योगा मैट स्लिप-प्रूफ है। 'झील से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके कुछ बनाना नया नहीं है। हम कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसका लोगों पर प्रभाव पड़े। हमें बुनाई आती थी और हमारे पास रॉ मटेरियल था। ऋतुराज और निर्मला ने हमारी मदद की.', मिताली दास ने कहा। ऋतुराज दीवान और निर्माली बरुआ की मदद से इन लड़कियों ने सस्टेनेबल योगा मैट

बढ़ती जा रही थी। इस झील में कई तरह के माइग्रेटरी पक्षी भी आते हैं। जलकुंभी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने का



बना लिया। ऋतुराज दीवान North East Centre for Training and Research and Simag Collectives Pvt Ltd के फ़ाउंडर है। ऋतुराज ने बताया कि एक मैट को बनाने में 3 हफ्ते तक का वक़्त लगता है और 38 महिलाएं अब इस काम से जुड़ चुकी हैं।

कैसे बनाता है जलकुंभी से योगा मैट?
रुमी दास ने बताया कि सबसे पहले जलकुंभी को पानी से निकालकर धूप में सुखाया जाता है। '12 किलो जलकुंभी सूखकर 2-3 किलो हो जाते हैं। सूखने के बाद उनके स्टेम को रूई के धागों के साथ बुनकर मैट तैयार किया जाता है। एक योगा मैट की कीमत 1200 से 1500 रुपये तक है। विश्व योग दिवस, 2021 को इस मैट को लॉन्च कर दिया गया।

जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल योगा मैट बना लिया है, इस बेहतरीन प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है, 'सीमांग'

अंटार्कटिका में सीलों पर रहने और खाने का संकट

शोध से पता चलता है कि सुरक्षित जगहों पर भी क्रेबेटर सीलों को पहले से ही प्रजनन और निवास स्थान के नुकसान का खतरा है। जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका में सीलों पर रहने खाने का संकट मंडरा रहा है। अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर में जलवायु परिवर्तन का असर एक समान नहीं है। गर्म में रहने वाली प्रजातियां उनके बदलते परिवेश के चलते अलग-अलग तरह से मुकाबला कर रहे हैं। जलवायु में हो रहे बदलाव जीवों की आबादी पर लगातार दबाव डाल रहा है। अब वैज्ञानिकों की एक टीम ने यहां रहने वाले सीलों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में पता लगाया है एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन से पता चलता है कि कैसे जलवायु परिवर्तन दुनिया के सबसे दूर स्थित महासागरों में से एक वेडेल सागर में रहने वाली सीलों को प्रभावित कर सकता है। न्यूजीलैंड के कैंटरबरी विश्वविद्यालय से जुड़ी टीम ने दक्षिणी महासागर के सीलों की खोज की। उपग्रह छवियों का उपयोग करके इस काम को हजारों वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया। वैज्ञानिकों ने कहा उनके निष्कर्षों का दिलचस्प हिस्सा इस बात से संबंधित है कि जलवायु परिवर्तन सीलों के इन प्रजनन स्थानों को किस तरह अलग-अलग तरीके से प्रभावित करेगा।

जलवायु परिवर्तन के कारण, क्रेबेटर सीलों के सामने आराम करने के लिए और अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए जगह खोजने की चुनौती होगी। डॉ वेज कहते हैं कि इन परिणामों में से बहुत आश्चर्यजनक यह है कि वेडेल समुद्र में, वेडेल सीलों के निकट भविष्य में कम से कम प्रभावित होने की उम्मीद है।

कोल इंडिया खिलाड़ियों के लिए तीन छात्रावासों के लिये फंड देगा

संवाददाता
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने देश में खेल के बुनियादी ढांचे को और बेहतर करने के उद्देश्य से 07 सितम्बर को नई दिल्ली में खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। एमओयू पर सीआईएल की ओर से विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) तथा युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से विजय कुमार, निदेशक (खेल) एवं सदस्य सचिव ने हस्ताक्षर किए। अनुराग सिंह ठाकुर, माननीय युवा मामले और खेल मंत्री एवं निमित्त प्रमाणिक, माननीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री, भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में यह एमओयू किया गया।

इस अवसर पर डॉ. अनिल कुमार जैन, सचिव (कोयला), रवि मिश्र, सचिव (खेल), प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष, सीआईएल, अतुल सिंह, संयुक्त वेज (खेल-विकास) एवं अन्य उपस्थित थे। समझौता ज्ञान के अंतर्गत सीआईएल अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के



तहत राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) की ओर से 75 करोड़ रुपये का योगदान दिया जायेगा। इस राशि का उपयोग खिलाड़ियों के लिए बने तीन अत्याधुनिक छात्रावासों के निर्माण के लिए किया जाएगा। वर्तमान में ओलंपिक और पैरालिंपिक के क्षेत्र में मिली सफलता को देखते हुये इस पहल को महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। विदित हो कि भारत का खेल के क्षेत्र में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है।

दिल्ली से सटा जंगल जिसे सैकड़ों साल से बचा रहे हैं स्थानीय लोग

सेंसी विश्वास
अरावली की पहाड़ियों में बसा हरियाणा का मांगर गांव इन दिनों चर्चा में है। चर्चा यहां के कंदराओं में मिले पाषाणकालीन पेंटिंग की हो रही है जिसे हाल ही में राज्य के पुरातत्व विभाग ने खोज निकाला है। दिल्ली और फरीदाबाद जैसे दो बड़े शहरों के बीच बसा यह जंगल का इलाका आसपास भौषण निर्माण के बावजूद भी अपना अस्तित्व बचाने में सफल रहा है। इसके पीछे यहां के स्थानीय लोगों का अथक प्रयास है, जिन्होंने विकास की विभिन्निका से अपना जंगल बचाए रखा है।



देश की राजधानी दिल्ली से सटे इलाके में ग्रामीण कई पीढ़ियों से अपने पवित्र वनों को खनन और रियल एस्टेट की नजर से बचाते आ रहे हैं। जैवविविधता के केंद्र होने के बावजूद इन स्थानों को वन संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित स्थान का दर्जा अभी तक नहीं मिल सका है। जानकारों को उम्मीद है कि इस स्थान पर नए पुरातात्विक खोज के बाद इसके संरक्षण के लिए समुदाय को अब कानून की मदद भी मिलेगी मांगर गांव के रहने वाले सुनील हर्षना कहते हैं कि उन्हें इन चित्रों की जानकारी पहले से थी। किशोरावस्था में सुनील मवेशी चराने के दौरान गर्मी से राहत पाने के लिए इन कंदराओं में आराम करते थे। हालांकि

उस समय उन्हें अंदाजा नहीं था कि पत्थरों पर उकेरे ये चित्र इतने महत्वपूर्ण हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरातत्व विभाग के उप निदेशक इस स्थान को पाषाणकाल का एक बड़ा स्थान मानते हैं। अब चर्चा इस स्थान को पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व का मानकर संरक्षण करने की चलने लगी है। मांगर गांव, हिमालय से भी पुराने अरावली पहाड़ श्रृंखला के बीच स्थित है। अरावली के पहाड़ श्रृंखला भारत के 700 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह गांव नई दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच स्थित है जहां गुर्जर समुदाय के लोग सदियों से निवास करते हैं। इनका मुख्य पेशा मवेशी चराना है। इनकी ऐतिहासिक जुड़े तलाशना मुश्किल है लेकिन बुजुर्गों से मिली जानकारी के मुताबिक ये सैकड़ों साल पहले यहां पलायन कर आए थे। हर्षना के मुताबिक पहले मांगर में रहने वाले अधिकतर लोग पशुपालन से अपनी जीविका चलाते थे। उन्होंने इस इलाके में वन प्रबंधन के लिए एक तंत्र भी बनाया ताकि जंगल के संसाधनों का उपयोग इस कदर हो कि ये खत्म न हो। और उनके मवेशियों को चारा मिलता रहे। जंगल के प्रबंधन का आधार मांगर बानों से जुड़ा है। यह पवित्र जंगल 274 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस जंगल को बचाने वाले गुदरिया दास बाबा की कहानी आज भी सुनाई जाती है। इस स्थान पर शिकार और पेड़ों की कटाई प्रतिबंधित है और अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो कोई दिव्य शक्ति है जो उस शख्स को इस पाप की सजा देती है। उस शख्स के लिए अगर किसी ने लकड़ी काटकर घर बनाया तो उस घर में आग लग जाती

उलीहातू गाँव के आदिवासी किसानों ने पशुपालन तकनीकों को देखा



रांची : बिस्सा कृषि विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण ले रहे उलीहातू गाँव के किसानों ने गुरुवार को पशु चिकित्सा संकाय स्थित कुक्कुट, सुकर एवं गन्ध फार्म का परिभ्रमण किया। किसानों को कुक्कुट (मुर्गी) फार्म में डॉ पवन कुमार ने मुर्गी के झारसीम, रेड दिव्यायान, कड़कनाथ सहित विभिन्न नस्लों की पहचान एवं विशेषता, आवास व आहार प्रबंधन की व्यावहारिक तकनीकों से अवगत कराया। इस फार्म के हेचरी यूनिट में मुर्गी के चूजे का निष्कासन तथा टीकाकरण की आवश्यकता की जानकारी दी।

गन्ध फार्म में डॉ पंकज कुमार, डॉ रविन्द्र कुमार ने टीकाकरण का सही समय एवं लाभ से अवगत कराया। परिभ्रमण कार्यक्रम का नेतृत्व एवं संचालन डॉ पंकज सेठ एवं डॉ बन्धुन उरॉव ने किया। प्रशिक्षण के तकनीकी सत्र में दूसरे दिन डॉ रास बिहारी साह ने बांस की उन्नत खेती एवं मूल्यवर्द्धन, डॉ एचसी लाल ने मशरूम उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकी एवं मूल्यवर्द्धन तथा श्रीमती स्मिता श्वेता ने समन्वित मछली पालन से संबंधित तकनीकी बातों की जानकारी दी।

EZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

● Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED